चीनी उद्योग कुछ शर्तों के साथ नियंत्रण मुक्त

अब राशन के लिए खुले बाजार से चीनी खरीदेगी केंद्र सरकार

- 10 फीसदी लेवी कोटे और खुले बाजार में बिक्री की मात्रा के प्रतिबंध हटे
- गन्ना मूल्य तय करने का विवादित मुद्दा राज्यों पर छोड़ा

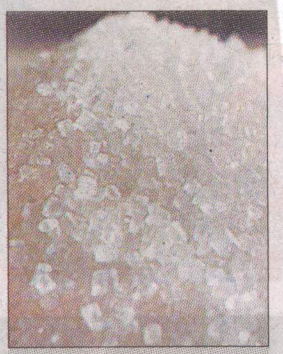

नई दिल्ली (ब्यूरो)। सरकार ने चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करने का फैसला किया है। अब चीनी मिलें खुले बाजार में अपनी सुविधा के हिसाब से चीनी बेच सकेंगी। मिलों पर लागू 10 फीसदी लेवी कोटे की बाध्यता भी खत्म कर दी गई है। अब सरकार पीडीएस के लिए बाजार भाव पर मिलों से चीनी खरीदेगी। लेकिन जनता को रियायती दर पर राशन की चीनी मिलती रहेगी। खरीद और बिक्री का अंतर सरकार खुद सब्सिडी के जरिए उठाएगी। इस पर करीब 5300 करोड़ रुपये का खर्च होगा। वहीं, गन्ना मूल्य निर्धारण के विवादित मुद्दे को राज्यों पर छोड़ दिया है। लेवी कोटे से मिलों को फिलहाल दो साल के लिए छूट दी गई है।

बृहस्पतिवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री केवी थॉमस ने कहा कि अब चीनी मिलें सरकार को सस्ती दर पर चीनी बेचने के लिए बाध्य नहीं होंगी। शेष पेज 13 पर ➲

संबंधित खबरें कारोबार पेज पर ➲

किस पर क्या असर

उपभोक्ता

- 10 फीसदी लेवी कोटे की चीनी अब खुले बाजार में बिकेगी, आपूर्ति बढ़ने से भाव कम हो सकते हैं।
- नियंत्रण हटने से लंबी अवधि में चीनी महंगी होने के आशंका भी है।

किसान

- चीनी मिलों को सालाना 3 हजार करोड़ रु की बचत होगी। इस लाभ का कुछ हिस्सा भी मिलों ने किसानों तक पहुंचाया तो गन्ने का बेहतर दाम मिल सकता है।
- मिलें अब सरकारी पाबंदियों के चलते नुकसान के नाम पर भुगतान में देरी नहीं कर पाएंगी।

मिल

- खुले बाजार में बिक्री की मात्रा भी सरकार तय करती थी। अब मिलें मर्जी से चीनी बेच पाएंगी। इससे उन्हें कारोबार प्रबंधन और कैश मैनेजमेंट में आसानी होगी।

चीनी उद्योग कुछ...

साथ ही खुले बाजार में चीनी बेचने पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी। उत्पाद शुल्क और आयात-निर्यात की नीति यथावत्त रहेगी। थॉमस ने इस फैसले को उद्योग, किसान और उपभोक्ता के हित में बताया है। उनका कहना है कि लेवी कोटे को खत्म करने का पूरा बोझ सरकार खुद उठा रही है। इसलिए महंगाई बढ़ने का सवाल ही नहीं है। सरकार पीडीएस के लिए अधिकतम 32 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर चीनी खरीदेगी। चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति (पीएमईएसी) के अध्यक्ष सी. रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इस समिति ने गत अक्तूबर में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। ताजा फैसला इस समिति की सिफारिशों की लाइन पर ही किया गया है।

अमर उजाला
5/4/13